Demand to recognise Shiksha Mitras as State employees

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): माननीय सभापति, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया।

महोदय, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की चयन प्रक्रिया, जिसमें ग्राम सभा से सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला व्यक्ति मैरिट के आधार पर शिक्षा मित्र बनता है। शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में पिछले 23 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन मायावती जी की सरकार द्वारा सभी शिक्षा मंत्रियों को दो वर्ष का बीटीसी प्रशिक्षण डाइट के माध्यम से कराया गया था। वर्तमान में शिक्षक की योग्यता के मानक एनसीटी द्वारा निर्धारित हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी शिक्षा मित्रों ने मानक पूरे कर लिए हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार इस महंगाई में शिक्षा मित्रों से 10,000 प्रति माह मानदेय पर कार्य करा रही है, जबकि बिहार, ओडिशा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि राज्यों में शिक्षा मित्रों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देकर समान कार्य, समान वेतन और अन्य सरकारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पूरे देश में खासकर उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र को राज्य कर्मचारी का दर्जा देकर समान कार्य, समान वेतन एवं अन्य सरकारी सुविधाएं प्रदान करे।